

□□□□□ □□□

जनसत्ता 20 जून, 2014 : आज की राजनीतिक बदलता स्वरूप अतीत की आंख से नहीं देखा जा सकता। जब भी हम पीछे देखते हैं तो बहुत से लोगों के कस्वर्णमि युग दीख पता है। उसके आलोक में जब हम वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के देखते हैं तो सब कुछ बुरा दीख पता है। प्रश्न यह है कि क्या हम फिर से इतिहास के अंधेरे गलियारे में लौटना चाहते हैं? या फिर हम वर्तमान के उन काले धबकों की ओर अंगुली उठा रहे हैं, जो हमें पछिना बना हुआ है? जिस प्रकार मोदी आगे बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि वे वर्तमान के आधार पर देश का भविष्य नहीं ना चाहते हैं, जो है उसमें से शुभ को स्वीकार करना चाहते हैं और जो बक़िर है उसका परहार या परषिकर करना चाहते हैं। वे पछिला सब कुछ नेस्तनाबूत करने के पक्ष में नहीं हैं। वे आगे के रास्ते की खोज में हैं।

यही सही मार्ग है। वर्तमान के धरा-ध्वस्त कर उसके मलबे पर न भवन का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऐसे प्रयास हुए हैं वे सभी सफल नहीं हुए। साम्यवाद की हथौड़ी से टूटे हुए और अपनी संस्कृति से भटके हुए समाज आज फिर संक्रमण की स्थिति में आ गए हैं। चुनावी चर्चा और भाषणों में अतिशयोक्ति का होना और जनादेश मलिन पर राजकाज संभालना दो अलग-अलग बातें हैं। शासन में पेश-बदल तो होंगे ही, पर साथ में नैरंतर्य का बना रहना भी जरूरी है। आखिर आज का भारत 1947 के भारत से बहुत भिन्न है और कई मायनों में श्रेष्ठ भी है। न शासन का ध्येय यह होना चाहिए कि समाज के बक़िरों को दूर करे और बक़िस के मार्ग की नई दिशा की खोज करे और उस पर अग्रसर हो। मोदी सरकार के प्रारंभ के ये दिन यही आशा जगाते हैं। देखना होगा कि कतिना हो पाता है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जो आशा की लहर चली थी वह कालांतर में निराशा के सलिसलिले में परिणत हो गई। क ओर तो लोगों की आशा और अपेक्षा बंती गई तो दूसरी ओर सत्तासीन लोगों में स्वार्थ का फेवकिले लगाता रहा। केंद्र में कुछ अपवादों के छोड़ कर कांग्रेस का वर्चस्व दशकों तक बना रहा। राज्यों में परिवर्तन तो हुआ, पर उन्हें भी केंद्र की चाबी ही चलाती रही। यह सचमुच पहली बार हुआ है कि अन्य यानी कई गैर-कांग्रेसी पार्टी पूरे बहुमत के साथ केंद्र में सत्तासीन हुई है। यों केंद्र में यह भाजपा का दूसरा दौर है। पहली दफा जब केंद्र में सत्तारू हुई थी, तो क्रीब दो दर्जन दलों का गठबंधन बनाना पड़ा था। फिर, उसके बाद जो दूसरी सरकारें बनीं, चाहे वे संयुक्त मोर्चे। तीसरे मोर्चे की थीं या कांग्रेस की, गठबंधन के सहारे ही बनीं। पछिले तीन दशक में यह पहली बार हुआ कि किसी दल के अपने बूते बहुमत हासिल हुआ है। यह भाजपा की अपूर्व सफलता है।

आज कांग्रेस में मौन छाया हुआ है और भाजपा नई ऊर्जा के साथ केंद्र की बागडोर संभाले हुए है। नश्चिति ही नई अपेक्षा जागी है।

क जीवंत समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवर्तन के प्रश्रय दे। अवश्य ही संस्कृति के क्राट आवागमन पर रोक लगाते हैं। उत्साह में हमने वगित में बाहर से कई मूल्यों, संस्थाओं, और व्यवहारों का आयात किया और हमारी समृद्ध संस्कृति ने उन्हें अपने ढंग से ही अंगीकर या फिर अस्वीकर किया। यह हमारी संस्कृति का लचीलापन है कि हम परिवर्तन के थपे के बीच भी अपना अस्तित्व बना रख सके।

आज की बदली हुई परिस्थिति में स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी के नेताओं का लोप होता जा रहा है। उनके नाती-पोतियों के जर्जर कुछ परिवार फिर से राजवंश का-सा व्यवहार करने लगे हैं। इस बीच कांग्रेस के बखिरने से राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ उभय भावति भी- कभी कांग्रेस के साथ-साथ कभी अलग-अलग। प्रांतीय राजनीतिक आविर्भाव भी हुआ है। जो गैर-कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री बने उनमें से वाजपेयीजी और मोदीजी के छोड़ कर

सभी कांग्रेस से टूटे हुए लोग थे। इसी कल में जब गैर-राजवंशी कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तभी देश उदारीकरण की ओर बढ़ा और आज वैश्वीकरण के अगुआओं में गिना जाता है।

जब दुनिया बीसवीं सदी की समाप्ति के समीप थी तब विकास प्रक्रिया के अवदानों का लेखा-जोखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिया गया। कोपेनहेगेन में 1995 में सामाजिक विकास का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में यूनेस्को की ओर से मुझे संयोजन का अवसर मिला।

इस सम्मेलन में पहली बार यह माना गया कि आर्थिक विकास अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है; उसे सामाजिक विकास के हित में कर्य करना चाहिए। यह कहा गया कि पछिल्ले वर्षों में आर्थिक विकास तो हुआ, पर सभी देश सामाजिक विकास की दृष्टि से पछि ही रहे। खासतौर से तीन बंटियों पर चर्चा व्यक्त की गई: बंती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार गरीबी, और सामाजिक वधितन। यह स्वीकार किया गया कि सामाजिक विकास की समस्या सार्वभौमिक है। वह सर्वत्र है, लेकिन इस घोर समस्या का समाधान प्रत्येक संस्कृति के संदर्भ में खोजना चाहिए। कतरह से तथाकथित गुजरात मॉडल का भी यही अभिप्रेत है। हमें प्रादेशिक संस्कृति और भूगोल के संदर्भ में समाधानों की खोज करनी होगी। मनरेगा जैसी अखिल भारतीय योजनाओं की विप्लवता का भी यही कारण है।

इसी सम्मेलन में भारत ने यह घोषणा की थी कि वह अपने सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करेगा। लेकिन 1995 में दिया गया यह वचन अब भी अधूरा है। इतना होते हुए भी हमारी साक्षरता का प्रतिशत नरंतर बढ़ रहा है, पर उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस ओर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

नई सरकार ने शासन सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री सरकार के विभिन्न महकमों की कार्य-प्रणाली समझ रहे हैं। रणनीतिक कक्ष (वार रूम) में बैठकें होने लगी हैं। भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए कदम उठा जा रहे हैं। कओर नया शक्तिशाली युद्धपोत राष्ट्र के समर्पण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर कश्मीर के सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मुआयना किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पंजीसी देशों से संबंध बेहतर बनाने की यात्रा पर चल पड़े हैं, और शुरुआत हुई है पंजीसी देश से। भूटान से भारत और भारत से भूटान का अनुप्रास मैत्री का नया अलंकरण बना है।

ऐसे अवसरों पर मीडिया की भी बड़ी जम्मेदारी है। जो कुछ दर्शनीय है उसे बाहरी दुनिया के लिए वर्णित करने की हो। मेरी राय में गलत है। प्रधानमंत्री की गुप्त बैठकों का जिक्र करना क्यों आवश्यक है? फिर जब प्रकट ही हो गया तो गुप्त क्या रहा? मीडिया की आपसी हो। में देश-हित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

यह सही है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। उन्हें पंद्रह-बीस दिन के कार्यकाल से आंक नहीं जा सकता। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के उनचास दिनों के कमकाज के पंचवर्षीय दर्पण में देख कर झुठलाना गलत था, वैसे ही पंद्रह-बीस दिनों के मोदी-राज की समीक्षा करना अनुचित होगा। कश्मिरे के रूटीन में बदलने दीजिए।

महत्त्वपूर्ण यह है कि ढीली पंजी सारी सरकारी मशीन में चुस्ती आई है। कुछ लोग बदले हैं तो कुछ के कार्य-क्षेत्र का विस्तार हुआ है- कम मंत्री ज्यादा महकमे! जाते-जाते पछिली सरकार ने जो नरिणय की। उनका पुनरीक्षण स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी।

जसि प्रकार राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की समीक्षा करवाई वैसे ही पुनरीक्षण की आज फिर आवश्यकता है। जहां एक ओर भारी-भरकम फीस लेकर नजि संस्थाएं वदियार्थियों के आकर्षण कर रही हैं वहीं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति, घसि-पट्टे पाठ्यक्रम, कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्ट राजनीति चिंता के वषिय हैं। पछिले वर्षों में कई आइआइटी और आइआइएम खुले हैं, पर वे अब भी नष्क्रिय हैं।

हर राज्य में एक मस खोलने की बात की जाने लगी है, पर दल्लि के एक मस का हाल यह है कि डॉ मनमोहन सहि का इलाज करने के लिए मुंबई के नजि अस्पताल से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। वाजपेयीजी के घुटनों का स्थानापन्न भी मुंबई के नजि अस्पताल में हुआ, और क्या भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर ने दल्लि के नेतागण अपने इलाज के लिए अपोलो या गुवां गांव स्थिति मेदांता में जाते हैं, और मरणासनन नरिभया के सगिपुर ले जाया जाता है। वयोवृद्ध मंत्री शीशराम ओला की मृत्यु भी मेदांता में हुई। नक्सलियों की गोलियों के शक्ति छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता वदियाचरण शुक्ल का उपचार भी मेदांता में हुआ, न कि एक मस में। क्या छवि होकर रह गई है एक मस की? जो कभी शहर से दूर गना जाता था वह एक मस आज शहर की गंदगी से घरा हुआ है और लोगों की पहली पसंद नहीं रह गया है।

यही हाल विश्वविद्यालयों का है। कई प्रदेशों में कुलपति की कुर्सी की नीलामी होती है। वह व्यक्ति इस पद को प्राप्त करता है, जो एक करोड़ के आसपास गुप्त धन नयोक्ता के देने की स्थिति में होता है। लेक्चरर तक कुलपति बन जाते हैं। इसी प्रकार अनुदान देने वाली शोध परिषदें खुल कर जातविाद के प्रश्रय दे रही हैं। करोड़ों रुपया उन लोगों या संस्थाओं पर लुटा रही है, जो शोध के नाम पर शून्य हैं। ऐसी संस्थाओं का बहुलीकरण का औचित्य ठीक से आंकने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि अच्छे भवषिय के निर्माण के लिए हमें शिक्षा पर बल देना होगा। शोध और उच्च शिक्षा में बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। अब तक हमारा जोर प्राथमिक शिक्षा और प्रौद्योगिक शिक्षा पर रहा है और उच्च शिक्षा के वरीयता देने से हम मुकुरते रहे हैं। सूचना क्रांति के इस युग में उच्च शिक्षा की अवहेलना आत्मघाती सिद्ध होगी। हमारी नई शिक्षामंत्री को इस संकट से उबरने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हम सबकी नजर अब आगत पर टिकी है।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>